www.tamsasanket.com
वर्ष: 05 || अंक 319 || लखनऊ
रविवार
22 फ़रवरी 2026 || पृष्ठ: 04 || मूल्य: ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र
लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित

मौसम
सूर्योदय: 06:37
सूर्यास्त: 06:03
अधिकतम: 29°00
न्यूनतम: 14°00

पेज 03

विशेष समाचार
राजनीतिक याचिकाओं पर सुप्रीम >> पेज 02
यूजीसी रेगुलेशन पर सवर्ण मोर्चा का ... >> पेज 04
रणवीर सिंह को मिली धमकी के मामले में ...

यूपी के किसानों के लिए सीएम योगी का 'होली गिफ्ट', बिचौलियों का खेल खत्म

460 करोड़ रुपये सीधे खातों में ट्रांसफर

योजना

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ-2025) के अंतर्गत 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का वितरण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 3500 लाभार्थी परिवारों को भी 175 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने बागपत, शामली, कासगंज, भदोही में उप कृषि निदेशक कार्यालय व मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, राजकीय भूमि संरक्षण केंद्र मऊरानीपुर झांसी में 50 शैय्या के छात्रावास

भवन तथा लखनऊ में स्मार्ट कृषि ब्यूरो स्टूडियो इकाई का शिलान्यास भी किया। उन्होंने विश्वास जताया कि अन्नदाता किसान उन्नत खेती के माध्यम से प्रदेश की समृद्धि में योगदान देते रहेंगे।

>> (शेष पेज 04 पर)

460 करोड़ रुपये किसानों के खाते में पहुंचे, बिचौलियों की भूमिका समाप्त

सीएम योगी ने कहा कि कल ही उत्तर प्रदेश सरकार का 2026-27 का बजट पारित हुआ है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बजट के माध्यम से प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं पास कराई गई हैं। जब बजट होता है तो लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे पैसा जाता है और उन्हें लाभ प्राप्त होता है। आज एक बटन दबाते ही 460 करोड़ रुपये किसानों के खाते में पहुंच रहे हैं, बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई। लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जनपदों में लाभार्थी परिवारों को इन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

आपदा मित्रों को मिला तीन साल तक पांच लाख का बीमा कवर

इन्हें इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट, आपदा मित्र ट्रेनिंग, मॉड्यूल आईडी, आईडी कार्ड व प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट में लाइफ जैकेट, सर्च टॉर्च, फर्स्ट-एड बॉक्स, सेफ्टी हेलमेट, चश्मा समेत 15 आइटम हैं। प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षित युवा स्वयंसेवकों का तीन वर्ष का जीवन व चिकित्सा बीमा करने का निर्णय लिया है।

"सीएम योगी ने कहा कि आपदा प्रबंधन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर आपदा मित्र हो सकता है। पीएम मोदी ने इस संबंध में बड़ा अभियान चलाया है। उत्तर प्रदेश ने पीएम की इस पहल को बढ़ाने का कार्य किया। 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवकों (एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट एंड गाइड) को प्रशिक्षित कर आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़े कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया है।"

अजित पवार के भतीजे का आरोप : प्लेन क्रैश बड़ी साजिश

दुर्घटना के समय कई धमाके हुए थे, विमान में पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे

आरोप

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली/बारामती/मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने शनिवार को अजित पवार के प्लेन क्रैश पर फिर सवाल उठाए। उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फेंस में स्क्रीन पर डेटा और फोटो दिखाए। उन्होंने कहा कि ब्लैक बॉक्स को लेकर शक जताया जा रहा था। उनके मुताबिक, दुर्घटना के समय सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ था, बल्कि कई धमाके हुए थे। विमान में सामान रखने वाली जगह पर अतिरिक्त पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे, जिससे आग भड़की। सभी पहलुओं की गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर साजिश की बात करें तो यह दो

तरह की हो सकती है, राजनीतिक या व्यावसायिक। अभी यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में किस तरह की साजिश शामिल है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। यह प्लेन VSR कंपनी का था। रोहित ने आरोप लगाया है कि अजित पवार प्लेन क्रैश के मामले को कुछ लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।

>> (शेष पेज 04 पर)

फास्ट न्यूज

बस-वैन में आमने-सामने की भिड़ंत, 5 की मौत

भिंड। भिंड में शुक्रवार देर रात बस और वैन आमने-सामने भिड़ गए। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन पूरी तरह पिचक गई। उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। गोहद चौराहा थाना प्रभारी मनीष धाकड़ के अनुसार, ईको वैन ग्वालियर से सवारियों को लेकर भिंड की ओर आ रहा था, जबकि बस भिंड से ग्वालियर की ओर जा रही थी।

एआई समिट में कांग्रेस का प्रदर्शन गलत:मायावती-अखिलेश

नई दिल्ली/मुंबई/गुजरात/। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा चीफ मायावती ने दिल्ली के भारत मंडपम में AI समिट में शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदर्शन को गलत बताया है। अखिलेश ने कहा, जब दुनियाभर से डेलीगेट्स आये हो तो ऐसा हंगामा नहीं करना चाहिए। सरकार से लड़ाई हमारा इंटर्नल मामला है, फॉरेन डेलीगेट्स के सामने हमारे देश का अपमान होता है। मायावती ने X पर लिखा- कांग्रेस का प्रदर्शन निन्दनीय है। अगर यह सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी, लेकिन AI समिट के दौरान ऐसा व्यवहार करना चिन्ता की बात है।

प. बंगाल में एसआईआर,हर सीट पर औसतन 19000 नाम हटे

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में दो-तीन माह ही बचे हैं। यहां अभी भाषण और रैलियों का शोर नहीं है। लेकिन, सियासत भरपूर गर्म है। कोलकाता के न्यू मार्केट से चांदनी चौक, न्यू टाउन से जेसप बिल्डिंग और मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से बर्द्धमान तक करीब 600 किमी के सफर में साफ हो गया कि अभी वोटर लिस्ट ही चुनावी रणभूमि बनी हुई है। कोलकाता के एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं।

दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट,लाल किले की सुरक्षा बढ़ाई

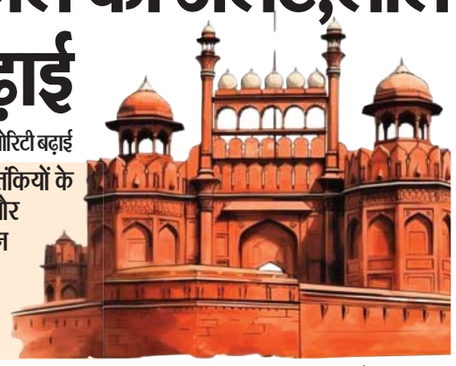

चांदनी चौक का मंदिर भी निशाने पर, धार्मिक-ऐतिहासिक जगहों की सिक्योरिटी बढ़ाई

"सूत्रों के मुताबिक चांदनी चौक इलाके का मंदिर भी आतंकियों के टारगेट पर है। इसके चलते दिल्ली के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। हालांकि इन सूचनाओं की अभी जांच की जा रही है, लेकिन एहतियात बरती जा रही है। साथ ही बम स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और क्विक रिएक्शन टीमों को तैनात की गई हैं।"

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद दिल्ली में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। लाल किले के आसपास आईईडी ब्लास्ट की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया है। खुफिया जानकारी के अनुसार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) ने भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों को अपने निशाने पर रखा है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय

एजेंसियां मिलकर स्थिति पर नजर रख रही हैं। संवेदनशील इलाकों में CCTV से निगरानी, वाहनों की जांच और अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की तुरंत पुलिस या आपात सेवाओं को सूचना देने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, यह कदम केवल सावधानी के तौर पर उठाए गए हैं। यह अलर्ट 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए एक कार बम धमाके के बाद आया है।

राजस्थान-एमपी समेत 4 राज्यों में 99.58 लाख नाम कटे

7 राज्यों-यूटी में एसआईआर की फाइनल लिस्ट पब्लिश, बंगाल में 28 फरवरी को लिस्ट आएगी

तमसा संकेत, एजेंसी

जयपुर/रायपुर। देश के 12 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का दूसरा फेज अपने अंतिम चरण में है। शनिवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और केरल की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश हुई। एमपी में 5.39 करोड़, राजस्थान में 5.15 करोड़, छत्तीसगढ़ में 1.87 करोड़ और केरल में 2.69 करोड़ वोटर के नाम फाइनल वोटर लिस्ट में है। चारों राज्यों में कुल 99,58,398 वोटर के नाम हटाए गए हैं। SIR प्रक्रिया में एमपी में 34.25 लाख, राजस्थान में 31.36 लाख, छत्तीसगढ़ में 24.99 लाख और केरल में 8.97 लाख लोगों के नाम कटे। अब तक कुल 7 राज्यों-UT की फाइनल

लिस्ट आ चुकी है। इससे पहले लक्षद्वीप, पुडुचेरी और गुजरात की अंतिम मतदाता सूची जारी हुई थी। आज गोवा और अंडमान-निकोबार की लिस्ट भी आ सकती है। वहीं तमिलनाडु में 23 फरवरी, पश्चिम बंगाल में 28 फरवरी और यूपी में 10 अप्रैल को फाइनल लिस्ट आएगी। 12 राज्यों-UT में वोटर लिस्ट के SIR में करीब 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं। ये प्रक्रिया 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई थी। 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी तक नाम जोड़ने, हटाने और सुधार के लिए आवेदन लिए गए, जिनका निपटारा करने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की जा रही है। 21 फरवरी- मध्य प्रदेश में कुल 5,39,81,065 वोटर के नाम दर्ज हैं। इस प्रक्रिया में राज्य में 34,25,078 वोटर के नाम कट चुके हैं। पूरी खबर पढ़ें...राजस्थान में 5,15,19,929 वोटर के नाम हैं। राज्य में 31,36,286 वोटर के नाम कट गए हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 1,87,30,914 वोटर दर्ज हैं। ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले फाइनल लिस्ट में 2,34,994 नए वोटर बढ़े हैं। केरल में कुल 2,69,53,644 वोटर्स हैं।

>> (शेष पेज 04 पर)

भारत-ब्राजील में क्रिटिकल मिनरल्स समझौता, पीएम मोदी बोले- 5 साल में 20 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य

ब्राजीली राष्ट्रपति ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की

दौरा

तमसा संकेत, एजेंसी

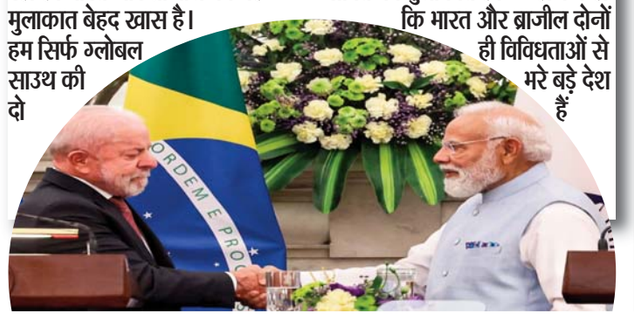

नई दिल्ली। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 18-22 फरवरी तक भारत के राजकीय दौरे पर हैं। आज उन्होंने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान लूला डी सिल्वा ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने यह भी कहा, 'आतंकवाद किसी धर्म या राष्ट्रीयता से जुड़ा नहीं है।' दूसरी ओर भारत और ब्राजील के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता मजबूत सप्लाई चेन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील ने अगले पांच सालों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स से जुड़ा समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख हिस्सा है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की निर्भरता कम करने, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करने और विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह समझौता दोनों देशों को कच्चे माल के निर्यातक से आगे बढ़ाकर प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और रिसाइक्लिंग में भागीदार बनाने पर जोर देता है। भारत की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग क्षमता ब्राजील के संसाधनों के साथ जोड़ी जाएगी। इन्वेस्टमेंट और जॉइंट वेंचर्स: भारतीय कंपनियां ब्राजील में निवेश कर सकती हैं, जबकि ब्राजील भारतीय टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेस चाहता है। ग्रीन ट्रांजिशन सपोर्ट: क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और AI से जुड़े टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी मिनरल्स की सुरक्षित आपूर्ति। पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की।

>> (शेष पेज 04 पर)

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा, 'मेरे प्रिय मित्र मोदी, इस देश में छठी बार आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत और ब्राजील की यह मुलाकात बेहद खास है। हम सिर्फ ग्लोबल साउथ की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें ही नहीं हैं, बल्कि यह एक डिजिटल शक्ति और एक नवीकरणीय ऊर्जा शक्ति की मुलाकात है।' उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील दोनों ही विविधताओं से भरे बड़े देश हैं

लूला बोले- ब्राजील को भारत से बहुत उम्मीदें

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा, 'भारत को लेकर ब्राजील की उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे, तो भारत-ब्राजील के रिश्ते और मजबूत होंगे।' उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर ग्लोबल साउथ को भी मजबूत करेंगे, ताकि दुनिया को दो बड़ी महाशक्तियों के बीच किसी नए शीत युद्ध जैसी स्थिति का सामना फिर कभी न करना पड़े।

ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर खोलेगा भारत

मोदी ने बताया कि भारत, ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्टक्चर के लिए एक सेंटर खोलने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, ' हम AI, सुपरकंप्यूटर, सेमीकंडक्टर और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में भी अपने सहयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं। दोनों देशों का मानना है कि टेक्नॉलाजी समावेशी होनी चाहिए। इसे दोनों देशों के लिए ब्रिज की तरह काम करना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'राष्ट्रपति लूला और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। राष्ट्रपति लूला की दूरदृष्टि और नेतृत्व से भारत-ब्राजील संबंधों को लंबे समय से लाभ मिला है। पिछले कुछ सालों में मुझे उनसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला है।'

मोदी बोले- अगले पांच सालों में द्विपक्षीय व्यापार 20 अरब डॉलर करना लक्ष्य

पीएम मोदी ने कहा, 'ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हम अगले पांच सालों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर से अधिक तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा व्यापार सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह विश्वास का प्रतीक है। राष्ट्रपति के साथ आए विशाल व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल इसी विश्वास को दिखाता है।' मोदी बोले, 'भारत-मर्कोसुर व्यापार समझौते का विस्तार हमारे आर्थिक सहयोग को और मजबूत करेगा। टेक्नॉलाजी और इनोवेशन के क्षेत्र में हमारा सहयोग दोनों देशों के साथ-साथ पूरे ग्लोबल साउथ के लिए भी महत्वपूर्ण है।'

भाजपा विधायक 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाए

कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने प्लान बनाकर पकड़ा

कार्रवाई

तमसा संकेत, एजेंसी

गडग (कर्नाटक)। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने शनिवार को भाजपा विधायक चंद्रू लामाणी को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। यह कार्रवाई गडग लोकायुक्त पुलिस ने एक ठेकेदार की शिकायत के आधार पर जाल बिछाकर की। लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार, यह रिश्वत मांग लघु सिंचाई विभाग के कामों से जुड़ी थी, जिसमें सड़क के किनारे रिटेनिंग वॉल (सहायक दीवार) बनाने का काम शामिल था। आरोप है कि विधायक ने काम करवाने के लिए ठेकेदार से 11 लाख रुपए की मांग की थी। जाल बिछाने की कार्रवाई के दौरान 5 लाख रुपए लेते समय उन्हें पकड़ा गया। शिरहट्टी विधानसभा क्षेत्र का

प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक के साथ उनके निजी सहायक मंजूनाथ वाल्मीकि और गुरु नाइक को भी इस मामले में हिरासत में लिया गया है। लोकायुक्त ने बयान में कहा कि तीनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है और जांच जारी है। अधिकारियों ने कहा कि आरोपी विधायक क खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(ए) और 7(एए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता विजय पुजार इस जिले के चिंचली गांव के रहने वाले क्लास-1 ठेकेदार हैं।

आदेश : प्रयागराज कोर्ट ने आदेश दिया, शंकराचार्य बोले- रामभद्राचार्य ने झूठा केस कराया

अविमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के यौन शोषण का केस दर्ज होगा

तमसा संकेत, एजेंसी

प्रयागराज। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन शोषण की FIR दर्ज करने के आदेश शनिवार को प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने दिए। जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश करके यह आरोप लगाए थे। कोर्ट में कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज हुए थे। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया की कोर्ट ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य

अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य
मुकुंदानंद शंकराचार्य शिष्य

मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात पर केस दर्ज करने के आदेश जारी किए। अदालत ने 13 फरवरी को अपना आदेश रिजर्व रखा था।

>> (शेष पेज 04 पर)

"अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा- रामभद्राचार्य से हम लोगों का वाकयुद्ध चलता रहता है। यह तो सभी लोग जानते ही हैं। उन्होंने हमारे ऊपर अपने चेले को आगे करके फर्जी मुकदमा करवाया है। वो चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ गोमाता की रक्षा की आवाज हम नहीं उठाएं। इसलिए हमारे ऊपर यह सब हो रहा है।"

शंकराचार्य बोले- रामभद्राचार्य ने अपने चेले से मुकदमा कराया

कोर्ट के फैसले के बाद शंकराचार्य ने कहा- यौन शोषण का केस फर्जी साबित होगा। ये बनाया हुआ मामला है। वह (आशुतोष महाराज) रामभद्राचार्य का एक चेला है। हिस्ट्रीशीटर है। उसने पहले भी लोगों के ऊपर झूठे केस किए हैं। वह लोगों को धमकाता है, धन उगाही करता है।

मोदी ने विश्वासघात किया : राहुल गांधी

खड़गे का आरोप- सरकार ट्रम्प की ट्रैप डील में फंसी

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। अमेरिकी टैरिफ डील पर विपक्ष फिर मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पीएम मोदी पर समझौता करने का आरोप लगाया। कहा कि उनका विश्वासघात अब उजागर हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि पीएम इस व्यापार समझौते में फिर से आत्मसमर्पण कर देंगे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना मोदी सरकार ने इतनी जल्दबाजी में एक ट्रैप डील में शामिल क्यों हुए, जिसने भारत से भारी रियायतें छीन लीं। बता दें अमेरिका ने 2 फरवरी को भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ

घटाकर 18% किया था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 20 फरवरी को बताया कि अमेरिका के साथ 'अंतरिम व्यापार समझौता' फरवरी के अंत तक फाइनल हो जाएगा। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ग्लोबल टैरिफ को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था।

सम्पादकीय

वैश्विक सम्मेलन में निर्लज्जता का प्रदर्शन

एआई इंपैक्ट समिट स्थल पर युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का अधनंगे होकर प्रदर्शन करना फूहड़ता की पराकाष्ठा है। निर्लज्जता केवल यह नहीं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत की अध्यक्षता वाले एक वैश्विक सम्मेलन में शर्ट उतारकर प्रदर्शन करना आवश्यक समझा, बल्कि यह भी है कि कांग्रेस के नेता इस अर्धनग्न प्रदर्शन की प्रशंसा कर रहे हैं और उसके प्रवक्ता टीवी चैनलों पर अपने लोगों की भद्दी हरकत का बिना किसी संकोच बचाव कर रहे हैं। यह कांग्रेस के वैचारिक दिवालिएपन का ही परिचायक नहीं, बल्कि इस सवाल का जवाब भी है कि वह लगातार चुनावी पराजय का सामना क्यों कर रही है और उसकी राजनीतिक जमीन क्यों खिसकती जा रही है। कांग्रेस जिस बेशर्मी से अपने कार्यकर्ताओं के शर्ट उतार विरोध प्रदर्शन के औचित्य को सही सिद्ध करने की कोशिश कर रही है, उससे यह भी रेखांकित होता है कि पीएम मोदी का विरोध करते-करते वह सरकार और देश विरोध के अंतर को पूरी तरह भूल चुकी है। लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रही कांग्रेस इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकती कि अंतरराष्ट्रीय महत्व के सम्मेलनों से देश का मान-सम्मान जुड़ा होता है और ऐसे आयोजन देश के कार्यक्रम होते हैं, न कि दल या सरकार विशेष के। कांग्रेस को यह पता ही होगा कि एआई सम्मेलन में एक दर्जन से अधिक देशों के शासनाध्यक्षों और लगभग 75 देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ चोटी की एआई कंपनियों और उद्योग जगत के जाने-माने प्रतिनिधि आए हैं। एक तो दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करने वाले आयोजन का स्थल दलगत संकीर्ण राजनीतिक हितों की पूर्ति का माध्यम नहीं हो सकता और दूसरे, यदि कांग्रेस को इस सम्मेलन से कोई शिकायत थी तो वह दिल्ली में ही अन्यत्र कहीं पर भी प्रदर्शन कर सकती थी। भारत मंडपम में छल-छद्म से घुसे अर्धनग्न प्रदर्शन करने वाले युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों की संख्या तो आठ-दस ही थी, लेकिन उन्होंने समूची कांग्रेस को बदनाम करने के साथ ही भारत को असहज करने की कुचेष्टा की। इस पर हैरानी नहीं कि एआई समिट के आयोजन स्थल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भोंडे प्रदर्शन से कांग्रेस के सहयोगी दल भी असहमति जता रहे हैं, लेकिन यह तय है कि कांग्रेस नेतृत्व यह आभास नहीं करने वाला कि उसने दुनिया भर से आए मेहमानों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया के समक्ष अपनी क्षुद्रता का ही परिचय दिया। ऐसे कृत्य राजनीतिक निकृष्टता ही कहे जाते हैं। लज्जा की बात केवल यह नहीं कि कांग्रेस ने मोदी सरकार की नीतियों से अपनी नाराजगी जताने के लिए एक बहुचर्चित अंतरराष्ट्रीय आयोजन स्थल को चुना, बल्कि यह भी है कि उसके प्रदर्शन का तरीका बहुत ही गंदा और जुगुप्सा पैदा करने वाला रहा।

राजनीतिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया

"एक-दूसरे को दोष देने की जगह सभी दलों को राजनीतिक मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए। दक्षिण भारत के कई नेताओं ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का कई बार इस्तेमाल किया है लेकिन इस याचिका में उनका जिक्र तक नहीं किया गया है।

इस देश का विपक्ष जनता की अदालत में मोदी सरकार से नहीं लड़ पा रहा है, इसलिए वो कानून की अदालत में उसे घसीटना चाहता है। अभी तक कई मौकों पर विपक्ष अपनी चाल में कामयाब रहा है लेकिन लगता है कि नए सीजेआई इस चाल को समझ चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक मामले में टिप्पणी की थी कि वो राजनीति के लिए अदालतों का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे सकते । उनका कहना था कि आजकल चुनाव के समय कुछ लड़ाई अदालतों में भी लड़ी जाती है । विपक्ष के कुछ बड़े वकील किसी न किसी मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़े रहते हैं । इन वकीलों का सुप्रीम कोर्ट में इतना प्रभाव है कि एक ही दिन में मामले की सुनवाई शुरू हो जाती है । अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ऐसे वकीलों ने मोदी सरकार के खिलाफ कई आदेश प्राप्त किये हैं । सीजेआई सूर्यकांत त्रिपाठी नहीं चाहते हैं कि कुछ वकील अपने एजेंडे के लिए माननीय अदालत का इस्तेमाल कर सके । सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को 12 प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सख्त रवैया अपनाया है । याचिकाकर्ताओं ने संवैधानिक नैतिकता के उल्लंघन को रोकने के लिए संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों और नौकरशाहों के लिए दिशा-निर्देश तय करने की मांग की थी । सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस नागरत्ना, और जस्टिस बागची की पीठ के सामने याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि देश का माहौल जहरीला हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ही इसे सुधार सकता है । वास्तव में याचिकाकर्ताओं ने असम, उत्तराखंड और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बयानों को आधार बनाकर हेट स्पीच के खिलाफ कठोर दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है । इसके अलावा इस याचिका में केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े और कुछ नौकरशाहों के बयानों को भी शामिल किया गया है । याचिकाकर्ता चाहते हैं कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों और नौकरशाहों के सार्वजनिक बयानों पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम अदालत द्वारा दिशानिर्देश बनाएं जाएं । माननीय अदालत ने इस याचिका को सुनने से ही मना कर दिया । अदालत का मानना है कि ये याचिका भाजपा के मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाने के लिए दायर की गई है । इस याचिका को देखकर लगता है कि सिर्फ भाजपा के मुख्यमंत्री ही हेट स्पीट देते हैं । माननीय न्यायाधीशों का यह भी कहना है कि ये याचिका अनुच्छेद-32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट आने के अधिकार का दुरुपयोग है । न्यायाधीशों का कहना है कि उच्च न्यायालय भी संवैधानिक न्यायालय होते हैं, उनके पास भी इसे सुनने का अधिकार है और उनके पास हमसे ज्यादा अधिकार हैं । अदालत का कहना है कि अनुच्छेद-32 के तहत अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट आने का अधिकार है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि राजनीतिक फायदों और नुकसान के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया जाए । खंडपीठ ने कहा कि याचिका में समस्या को उजागर करते हुए कुछ चुनिंदा व्यक्तियों पर निशाना साधा गया है । उनका कहना था कि यह याचिका पूर्ण रूप से एकतरफा दिखाई देती है । इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो नियमित रूप से हेट स्पीच देते हैं । याचिका को देखकर लगता है कि सिर्फ इसमें शामिल लोग ही हेट स्पीच देते हैं । माननीय अदालत का कहना है कि याचिकाकर्ताओं को इसका ध्यान रखना चाहिए था कि याचिका सिर्फ कुछ व्यक्तियों को निशाना बनाने के लिए न हो । सीजेआई ने कहा कि मामला महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए निष्पक्ष याचिका दायर की जानी चाहिए । वास्तव में अदालत ने याचिकाकर्ताओं की मंशा को समझ लिया है । अदालत को समझ आ गया है कि कुछ लोग अपने एजेंडे के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं । अगर इन्हें सच में हेट स्पीच से परेशानी होती तो ये लोग पार्टी विशेष को टारगेट नहीं करते । वास्तव में याचिकाकर्ताओं का उद्देश्य हेट स्पीच न होकर भाजपा के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आदेश पारित करवाना है । क्या वो नहीं जानते कि हेट स्पीच सभी पार्टियों के नेताओं द्वारा की जाती है । जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा को लेकर हेट स्पीच की बाढ़ आई हुई है । देखा जाए तो नफरती भाषण खत्म करने के नाम पर याचिका दाखिल करने वाले खुद ही नफरत से भरे हुए लोग है । इनकी नफरत ही इन्हें अदालत ले आई है । इनकी याचिका अपने आप में एक हेट स्पीच है जो कहती है कि भाजपा के तीन मुख्यमंत्री ही हेट स्पीच कर रहे हैं । कितनी अजीब बात है कि दुराग्रह से ग्रस्त लोग हेट स्पीच बंद करवाना चाहते हैं जबकि यही लोग हेट स्पीच वालों के समर्थन में खड़े रहते हैं । हेट स्पीच को लेकर जब किसी के ऊपर कार्यवाही की बात आती है तो यही बड़े-बड़े वकील उनके लिए अदालत में खड़े हो जाते हैं । यही कारण है कि किसी के खिलाफ भी कार्यवाही नहीं हो पाती है । तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र उदयनिधि मारन ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी बता दिया था और कहा था कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि इसे खत्म कर देना चाहिए । इसके अलावा उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर कई बार जहर उगला है । अगर यही बात उन्होंने इस्लाम को लेकर कही होती तो यही याचिकाकर्ता उनके खिलाफ अदालत में खड़े होते । अजीब बात है कि एक धर्म को खत्म कर देने वाला बयान इन्हें हेट स्पीच नहीं लगता है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे ने भी हिन्दू धर्म को लेकर इतने कड़वे बोल बोले हैं कि उन्हें दोहराना अच्छा नहीं लगता। अगर भाजपा के नेता विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हेट स्पीच करते हैं तो ये काम दूसरी तरफ से भी होता है। अजीब बात तो यह है कि सबसे ज्यादा नफरती बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया जाता है। एक तरह से उन्हें सीधी गाली देने का चलन विपक्षी नेताओं ने शुरू किया हुआ है। इसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी भाजपा नेताओं द्वारा भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल यह है कि यह कौन तय करेगा कि कौन ज्यादा नफरत फैला रहा है। पिछले कुछ समय से राजनीतिक माहौल में ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, इसलिए एक-दूसरे के खिलाफ नफरती भाषा बढ़ती जा रही है। इस दौड़ में कोई पीछे नहीं है, इसलिए किसी एक पक्ष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। याचिकाकर्ताओं ने सिर्फ एक पक्ष के लोगों को नफरती बयान देने से रोकने की गुहार लगाई है। वो चाहते हैं कि अदालत उनको रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करे । अगर सुप्रीम कोर्ट दिशानिर्देश जारी कर देता है तो उसके उल्लंघन को रोकने की जिम्मेदारी किस पर होगी। देखा जाए तो इन दिशानिर्देशों को लागू करने की जिम्मेदारी भी अदालत पर ही आ जायेगी। इसके बाद अदालत में इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामलों की बाढ़ आ सकती है।

राजेश कुमार पासी

जन सुराज का...

अशोक भाटिया

सुप्रीम कोर्ट की फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले 'मुफ्त की रेवड़ियां' बांटने यानि फ्रीबीज पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर वे इसी तरह 'मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली। । । ' जैसी सुविधाएं देते रहे, तो डेवलेपमेंट के लिए पैसे कहां से बचेगा? इस साल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 'तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड' ने एक याचिका दायर कर उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति पर गौर किए बिना हर किसी को फ्री बिजली देने करने का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद 'मुफ्त की रेवड़ियां' बांटने का मुद्दा एक बार फिर लाइमलाइट में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनाई के दौरान कहा कि कई सरकारें करोड़ों रुपये विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर सब्सिडी देने में खर्च कर रही हैं, जबकि वे बजट घाटे का सामना कर रही हैं और विकास एवं बुनियादी ढांचे के लिए धन की कमी की शिकायत कर रही हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अंधाधुंध मुफ्त सहायता, विशेष रूप से उन लोगों को जो उपयोगिताओं और सेवाओं के लिए भुगतान करने में सक्षम हैं, इससे एक ऐसी संस्कृति का जन्म हुआ है जो काम न करने को पुरस्कृत करती प्रतीत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को मुफ्त सुविधाएं देने की संस्कृति की कड़ी आलोचना करते हुए गुरुवार को कहा कि देश के आर्थिक विकास में बाधा डालने वाली ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार करने का समय आ गया है। शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर राज्य गरीबों की मदद करते हैं, तो यह बात पूरी तरह से समझ में आती है। देश के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची एवं न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि अधिकतर राज्यों का राजस्व घाटे में हैं, लेकिन वे विकास की अनदेखी करते हुए इस तरह की मुफ्त सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि इस तरह की मुफ्त सुविधाएं देने से देश के आर्थिक विकास में बाधा पैदा होती है और राज्यों को सभी को मुफ्त भोजन, साइकिल और बिजली देने के बजाय रोजगार के अवसर खोलने के लिए काम करना चाहिए। हालांकि, अदालत ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सरकार के नेतृत्व वाली बिजली वितरण कंपनी की मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखने वाली याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया। बिजली वितरण कंपनी ने विद्युत संशोधन नियम, 2024 के एक नियम को चुनौती दी है। पीठ ने कहा, 'भारत में हम कैसी संस्कृति विकसित कर रहे हैं? यह समझ में आता है कि कल्याणकारी कदमों के तहत आप उन लोगों को (निःशुल्क) सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहते हैं, जो बिजली शुल्क चुकाने में असमर्थ हैं। 'गौरतलब है कि इन मुद्दों में से पहला 'रेवाड़ी' के नाम से जानी जाने वाली मुफ्त योजनाओं का मुद्दा है, जिसे हाल ही में दायर किया गया था, लेकिन पहली याचिका 2013 में मुफ्त उपहारों को रोकने के लिए दायर की गई थी, यहां तक कि 'रेवाड़ी' शब्द प्रचलन में आने से पहले ही। तमिलनाडु में पार्टियां भविष्य की सरकार से मुफ्त रंगीन टीवी, मिक्सर और अन्य वस्तुओं के साथ मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। इस भ्रष्टाचार को रोकने की मांग करने वाले मामले को भी सुलझा लिया गया। उस समय, सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त योजना को रोकने के लिए क्या निवारक उपाय किए जाने चाहिए, विशेष रूप से चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल को इस तरह की घोषणाएं करने से कैसे रोका जाए, इस पर सरल नियमों को अनिवार्य और लागू नहीं किया था। आगे कुछ नहीं किया गया, इसलिए अब समय आ गया कि आप और खुद प्रधानमंत्री जैसे दलों को एक कुंद बयान देना चाहिए कि 'देशवासियों को रेवाड़ी की आजादी की आदत हो रही है'। भाजपा के एक सहानुभूतिपूर्ण वकील के माध्यम से रेवाड़ी के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी, लेकिन कई सुनवाई के बाद इसे दो के बजाय तीन न्यायाधीशों को सौंपने का फैसला किया गया। इस बीच, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों पर 'घोषणापत्र में ही मुफ्त योजनाओं पर होने वाले खर्च का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने और उन्हें यह बताने के लिए प्रतिबंध लगा दिया कि बोझ कैसे कवर किया जाएगा'। दूसरा विषय है हेट स्पीच, भले ही प्राचीन काल से नफरत और नफरत के शब्द सुने जाते आए हैं और कांग्रेस के समय सज्जन कुमार और अन्य जनप्रतिनिधि भी इसके लिए दोषी थे, लेकिन मामला वापस कोर्ट में चला गया क्योंकि इसने नफरत फैलाने वाले भाषणों की भीड़ को दबा दिया है, नफरत फैलाने वालों को भी दबा दिया है। हाल ही में जो 'विवादित रील' चर्चा में रही है, उसे भले ही असम के मुख्यमंत्री या असम भाजपा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया हो, लेकिन ये मुख्यमंत्री बंदूक तान रहे हैं उसके बाद के दिनों में, लाखों भारतीयों को पता चल गया है कि विज्ञापन किसके खिलाफ था। हालांकि, अदालत ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले प्रशांत भूषण जैसे कार्यकर्ताओं से कहा कि वे इस मुद्दे पर ऐसे किसी भी पक्ष के खिलाफ याचिका न लाएं। याचिका को संतुलित करें।

रणनीतिक...

डॉ.बालमुकुंद पाण्डेय

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता : सामयिक मूल्यांकन

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हाल ही में घोषित व्यापार समझौता लगभग ग्यारह महीनों तक चले कूटनीतिक तनाव और अनिश्चितता के बाद सामने आया है। इस अवधि में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध पिछले दो दशकों में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुँच गए थे। ऐसे परिदृश्य में यह समझौता केवल व्यापारिक हितों तक सीमित न होकर भारत की आर्थिक नीति, ऊर्जा सुरक्षा तथा वैश्विक रणनीतिक स्थिति को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम बनकर उभरा है। इस समझौते का केंद्रीय आर्थिक पक्ष अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ में उल्लेखनीय कटौती से संबंधित है। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार भारत पर लागू कुल 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। यह टैरिफ संरचना दो भागों में विभाजित थी—25 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ और रूस से कच्चे तेल के आयात के कारण लगाया गया 25 प्रतिशत पेनल्टी टैरिफ। पेनल्टी टैरिफ का हटना भारत के लिए केवल आर्थिक राहत नहीं है बल्कि यह दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का भी संकेत देता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। वर्ष 2025 में भारत का अमेरिका को निर्यात लगभग 100 अरब डॉलर रहा। टैरिफ में कटौती के परिणामस्वरूप भारतीय निर्यात में 20 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही है। टेक्सटाइल, रत्न एवं आभूषण, ऑटोमोबाइल कलपुर्जे, फार्मास्यूटिकल्स तथा इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे क्षेत्र इस समझौते से विशेष रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। अमेरिकी उपभोक्ता बाजार में भारतीय उत्पादों की कीमतों में अपेक्षित कमी से निर्यात विस्तार और रोजगार सृजन की संभावनाएँ बढ़ेंगी। टेक्सटाइल क्षेत्र पर इस समझौते का प्रभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय हो सकता है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में यह उद्योग बड़े पैमाने पर श्रम-आधारित है। अमेरिकी बाजार में मांग में वृद्धि से इन राज्यों में उत्पादन, आय और रोजगार के अवसरों में वृद्धि संभव है। वित्तीय बाजारों की सकारात्मक प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि निवेशक इस समझौते को अल्पकाल में भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए अनुकूल मान रहे हैं। हालाँकि इस समझौते के आर्थिक लाभों के साथ कुछ रणनीतिक और संरचनात्मक चिंताएँ भी जुड़ी हुई हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण भारत की ऊर्जा नीति में संभावित परिवर्तन है। अमेरिकी पक्ष के अनुसार भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद को सीमित करने पर सहमति जताई है, जिसके परिणामस्वरूप पेनल्टी टैरिफ को हटाया गया। इसके विकल्प के रूप में भारत द्वारा अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से तेल आयात बढ़ाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में रूस भारत का प्रमुख कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रियायती दरों पर रूसी तेल के आयात ने भारत को अपनी ऊर्जा लागत नियंत्रित करने और घरेलू महंगाई पर अंकुश लगाने में सहायता की। वर्ष 2024–25 में भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत थी।

भाषा के साथ खत्म हो जाती है मौलिक सभ्यता

हर वर्ष 21 फरवरी विश्व में मातृभाषाओं के आहत स्वाभिमान और उसके खोए हुए आत्मविश्वास की वापसी का संकल्प और स्वप्न लेकर आती है। 1999 में यूनेस्को ने इस तिथि को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यह इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि हम सांस्कृतिक वैविध्य को तभी बचा सकते हैं, जब विभिन्न भाषाओं को बचा पाएंगे। अंतर-राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की पृष्ठभूमि पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के 'बांग्ला भाषा आंदोलन' में निहित है। पाकिस्तान ने उस पर उर्दू थोप दी थी। इस निर्णय से असंतुष्ट ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों और कुछ सामाजिक संस्थाओं ने 21 फरवरी, 1952 को विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चला दीं। इसमें कई छात्र मारे गए। इन छात्रों की स्मृति में यूनेस्को ने 1999 में इस दिन को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मानने की घोषणा की। उसने मातृभाषा को मदर टंग के रूप में नहीं, बल्कि मदर लैंग्वेज के रूप में लिया। यानी आपकी मूल भाषा, जिसे प्राथमिक भाषा भी कहा जा सकता है। यह भाषा हमारी पहचान और हमारे मानसिक व्यक्तित्व के निर्माण का आधार होती है। मातृभाषा का महत्व इसलिए है, क्योंकि हर भाषा की संरचना के सामाजिक-सांस्कृतिक स्रोत होते हैं। भाषा हमें अपने इतिहास, मिथक और परंपरा से जोड़ती है। यह जुड़ाव ही सामूहिक अस्मिता बनकर बेहद मूल्यवान बन जाता है। हमारी संस्कृति की धड़कन हमारी भाषा की अवधारणाओं, मिथकों, बिंबों और प्रत्ययों में मौजूद रहती है, लेकिन विडंबना यह है कि नए वैश्विक परिदृश्य और तेजी से परिवर्तित होती परिस्थितियों में अनेक भाषाएं अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। संप्रेषण के नए युग में सांस्कृतिक वैविध्य और अन्य विविधताओं को मिटाकर एक समान संस्कृति, समान सभ्यता और समान रुचियों के 'विश्व मॉडल' की संकल्पना ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की भाषाओं के समक्ष चुनौतियां पैदा की हैं। विश्व की अनेक भाषाओं पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कई भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं।

■ कुमुद शर्मा

जरा हटके

सुप्रीम कोर्ट ने...

ललित गर्ग

डिजिटल युग में मातृभाषाओं को बचाना बड़ी चुनौती

21 फरवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस केवल मातृभाषा संस्कृति को बचाने का अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि मानवता की सांस्कृतिक आत्मा का उत्सव है। वर्ष 2026 में इसकी मुख्य थीम "बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं की आवाज़" है, जो यह संकेत देती है कि भविष्य की भाषाई दिशा युवा पीढ़ी तय करेगी। यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस दिवस की 25वीं वर्षगांठ-रजत जयंती का प्रतीक है। वर्ष 1999 में यूनेस्को द्वारा इसकी घोषणा की गई और 2000 से इसे वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। इस वर्ष का फोकस 13 से 18 वर्ष के युवाओं को भाषाई विविधता के संरक्षण, मातृभाषा में शिक्षा के विस्तार और डिजिटल युग में भाषाओं की भूमिका पर सक्रिय संवाद के लिए प्रेरित करना है। मातृभाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती, वह मनुष्य के मन, मस्तिष्क और संवेदनाओं की प्रथम अभिव्यक्ति है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह किसी औपचारिक शिक्षा से पहले अपनी माँ की ध्वनियों, लोरियों और संवादों के माध्यम से भाषा का संस्कार ग्रहण करता है। यही भाषा उसकी सोच, उसकी रचनात्मकता और उसकी पहचान का आधार बनती है। शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होने पर बच्चों की समझ, विश्लेषण क्षमता और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। फिर भी वैश्विक स्तर पर लगभग 40 प्रतिशत बच्चों को उस भाषा में शिक्षा नहीं मिलती जिसे वे बोलते या समझते हैं। इस दिवस का ऐतिहासिक संदर्भ हमें 21 फरवरी 1952 की उस त्रासदी की याद दिलाता है जब पूर्वी पाकिस्तान में अपनी मातृभाषा बांग्ला के सम्मान के लिए छात्रों ने आंदोलन किया और गोलीबारी में अनेक युवा शहीद हो गए। बाद में यही पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बना। उन शहीदों की स्मृति में यह दिवस भाषाई अधिकारों और अस्मिता का प्रतीक बन गया। यह हमें सिखाता है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता का आधार है। वर्ष 2026 की थीम युवाओं की भागीदारी को केंद्र में रखती है। आज का युवा डिजिटल संसार में जी रहा है। सोशल मीडिया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑनलाइन शिक्षा उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मातृभाषाओं के लिए पर्याप्त स्थान है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ओर तो विलुप्तप्राय भाषाओं के शब्दकोश, ध्वनि-संग्रह और अनुवाद प्रणाली विकसित कर उन्हें पुनर्जीवित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर यदि तकनीक कुछ सीमित भाषाओं तक सिमट जाए तो भाषाई असमानता और गहरी हो सकती है। इसलिए युवाओं को तकनीक का उपयोग मातृभाषा सशक्तिकरण के लिए करना होगा-ऐप, ब्लॉग, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल और डिजिटल पुस्तकालयों के माध्यम से अपनी भाषाओं को वैश्विक मंच देना होगा। यूनेस्को का मानना है कि स्थायी समाज के लिए सांस्कृतिक और भाषाई विविधता बहुत जरूरी है। शांति के लिए अपने जनादेश के तहत यह संस्कृतियों और भाषाओं में अंतर को बनाए रखने के लिए काम करता है जो दूसरों के लिए सहिष्णुता और सम्मान को बढ़ावा देते हैं। बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक समाज अपनी भाषाओं के माध्यम से अस्तित्व में रहते हैं जो पारंपरिक ज्ञान और संस्कृतियों को स्थायी तरीके से प्रसारित और संरक्षित करते हैं। भाषाई विविधता लगातार खतरे में पड़ती जा रही है क्योंकि अधिकाधिक भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं। मातृभाषा जीवन का आधार है, यह एक ऐसी भाषा होती है जिसे सीखने के लिए उसे किसी कक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं, वही व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। लेकिन मानव समाज में कई दफा हमें मानवाधिकारों के हनन के साथ-साथ मातृभाषा के उपयोग को गलत भी बताया जाता रहा है। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह चुनौती और अवसर दोनों है। पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार पिछले कुछ दशकों में सैकड़ों भाषाएँ लुप्त हो चुकी हैं। यह केवल शब्दों का खो जाना नहीं, बल्कि परंपराओं, लोककथाओं, लोकगीतों और जीवनदृष्टि का विलुप्त होना है। यदि नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा से विमुख हो जाएगी तो सांस्कृतिक जड़ों से उसका संबंध कमजोर हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में बहुभाषी शिक्षा को प्रोत्साहन मिले, स्थानीय साहित्य और लोकसंस्कृति को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए, और युवाओं को अपनी भाषा में अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान किए जाएँ। आज एक बड़ा भ्रम यह है कि केवल विदेशी भाषा ही विकास का मार्ग है। निस्संदेह वैश्विक संपर्क के लिए अन्य भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करें। मातृभाषा में शिक्षा से ही मौलिक चिंतन और नवाचार संभव है। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 ने भी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने पर बल दिया है। यह निर्णय वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है, क्योंकि जब विद्यार्थी अपनी सहज भाषा में सीखता है तो वह केवल जानकारी ग्रहण नहीं करता, बल्कि उसे आत्मसात करता है। हमारे देश में मातृभाषाओं के प्रति अनेक प्रकार के भ्रम फैले हैं, जिनमें एक भ्रम है कि अंग्रेजी विकास और ज्ञान की भाषा है। जबकि इस बात से यूनेस्को सहित अनेक संस्थानों के अनुसंधान यह सिद्ध कर चुके हैं कि अपनी भाषा में शिक्षा से ही बच्चे का सही एवं सर्वांगीण मायने में विकास हो पाता है।

भारत-पाकिस्तान और इंग्लैंड को टक्कर दी, एसोसिएट देशों की मांग- हमें ज्यादा मैच चाहिए

टी-20 वर्ल्डकप में एसोसिएट देशों का बेहतर प्रदर्शन

नई दिल्ली, एजेंसी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एसोसिएट देशों ने अपने प्रदर्शन से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। नीदरलैंड, नेपाल, अमेरिका, इटली और स्कॉटलैंड जैसी टीमों ने क्रिकेट के दिग्गजों को हार की कगार पर खड़ा कर दिया। आंकड़े गवाह हैं कि अब एसोसिएट और फुल मेंबर देशों (टेस्ट खेलने वाले देश) के बीच का अंतर तेजी से कम हो रहा है। हालांकि, इन टीमों के कोच और खिलाड़ियों का दर्द एक ही है उन्हें बड़े देशों के खिलाफ खेलने के पर्याप्त मौके नहीं मिलते। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि आईसीसी और बड़े बोर्ड्स अक्सर छोटी टीमों को नजरअंदाज करते हैं। 2024 वर्ल्ड कप में सुपर-8 तक पहुंचने वाली अमेरिका की टीम ने इस वर्ल्ड कप तक किसी बड़े देश के खिलाफ एक भी मैच नहीं खेला। इसी तरह, 2022 में साउथ अफ्रीका को हराने वाली नीदरलैंड की टीम ने अगला टी-20 मैच सीधे 479 दिनों के बाद खेला। मौके कम मिलने के बावजूद इन टीमों के बेहतर प्रदर्शन की बड़ी वजह दुनियाभर में चल रही टी-20 लीग्स हैं। एंड्रीज गौस (यूएसए) और मोहम्मद वसीम (यूएई) जैसे खिलाड़ी राशिद खान, निकोलस पूरन और क्रिस वोक्स जैसे दिग्गजों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं। साथ ही, स्टुअर्ट लॉ (नेपाल), गैरी कर्स्टन (नामीबिया) और लालचंद राजपूत (यूएई) जैसे अनुभवी कोचों की मौजूदगी ने इन टीमों की सोच को प्रोफेशनल बनाया है।

66 नेपाल की टीम इंग्लैंड के खिलाफ 185 रनों का पीछा करते हुए जीत के बेहद करीब थी। लोकेश बम की 15 गेंदों पर 35 रनों की पारी ने इंग्लैंड की सांसें अटका दी थीं, लेकिन सैम करन ने मैच बचा लिया। उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट लिए।

भारत और पाकिस्तान के खिलाफ दिखी टक्कर

इस वर्ल्ड कप में कई ऐसे मौके आए जब बड़ी टीमें उलटफेर का शिकार होते-होते बचीं। नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम 148 रन का पीछा करते हुए 114 रन पर उसके 7 विकेट गिर गए थे। मैक्स ओ'डॉड से एक कैच छूटा और फहीम अशरफ ने अंत में छक्का जड़कर मैच पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। भारत के खिलाफ अमेरिका ने भी शानदार शुरुआत की थी और 10वें ओवर तक भारत का स्कोर 63/4 कर दिया था। शुभम रांजणे ने अगर सूर्यकुमार यादव का कैच न छोड़ा होता, तो नतीजा कुछ और हो सकता था। सूर्या ने 84 रनों की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई।

नेट प्रैक्टिस से नहीं, मैच खेलने से आएगा कॉन्फिडेंस

UAE के कोच लालचंद राजपूत ने एसोसिएट देशों की समस्या पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा,'आप कितनी भी नेट प्रैक्टिस कर लें, लेकिन जब तक आप मैदान पर मुश्किल स्थितियों (जैसे 80/5 का स्कोर) का सामना नहीं करेंगे, तब तक दबाव झेलना नहीं सीखेंगे। जब आप अच्छी टीमों के खिलाफ खेलेंगे, तभी आप में यह भरोसा आएगा कि अगली बार ऐसी स्थिति में हम जीत सकते हैं।' वहीं, पहली बार खेल रही इटली की टीम ने भी इंग्लैंड के खिलाफ 203 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जमकर लड़ाई लड़ी और मैच को आखिरी 2 ओवरों तक ले गए।

फुल मेंबर्स का सिस्टम छोड़कर दूसरे देशों से खेलने का फायदा

एसोसिएट टीमों की मजबूती का एक और स्तंभ वे खिलाड़ी हैं जो अपने मूल देश (फुल मेंबर) में मौके न मिलने पर दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। रोलोफ वैन डर मर्वे (साउथ अफ्रीका से नीदरलैंड) और ग्रांट स्टीवर्ट (इंग्लैंड से इटली) इसके बड़े उदाहरण हैं। वैन डर मर्वे ने अब सुनील नरेन से ज्यादा वर्ल्ड कप विकेट चटकाए हैं। यह 'म्युचुअल अरेंजमेंट' छोटी टीमों को अनुभव प्रदान कर रहा है।

ऑस्ट्रेलिया ने टी-20 वर्ल्डकप में आखिरी मैच जीता

ओमान को 9 विकेट से हराया, मार्श-हेड ने 93 रन जोड़े

मुंबई, एजेंसी

ऑस्ट्रेलिया ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 जीत के साथ खत्म किया। टीम ने शुक्रवार को आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में ओमान को 9 विकेट से हरा दिया। कैंडी के पल्लेकेले स्टेडियम में पहले बैटिंग करने उतरी ओमान 104 रन पर सिमट गई। मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड ने 93 रन की पार्टनरशिप कर कंगारू टीम को जीत दिला दी। ऑस्ट्रेलिया के लिए गेंदबाजी में लेग स्पिनर एडम जम्पा ने 4 विकेट लिए। ग्लेन मैक्सवेल और जैवियर बार्टलेट को 2-2 विकेट मिले। कप्तान मार्श ने फिफ्टी लगाई, वहीं ट्रैविस हेड 32 रन बनाकर आउट हुए। ओमान के लिए वसीम अली ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप-बी में श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ हार कर बाहर हो गई। टीम ने आयरलैंड और ओमान को हराया, लेकिन ये अगले राउंड में पहुंचने के लिए काफी नहीं था। टीम 2009 के बाद पहली बार ग्रुप स्टेज को भी पार नहीं कर सकी। 9वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने पहला विकेट गंवाया। ओवर की पहली बॉल शकील अहमद ने गुड लेंथ पर फेंकी। ट्रैविस हेड बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद हवा में खड़ी हो गई। शकील खुद ही गेंद के नीचे आए और कैच पकड़ लिया। हेड ने 32 रन बनाए और कप्तान मिचेल मार्श के साथ 93 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। 105 रन के टारगेट के सामने ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही ओवर में 14 रन बना दिए। शफीक जान के खिलाफ पहले ओवर में मिचेल मार्श ने 3 चौके लगाए। मार्श के साथ नॉन-स्ट्राइकर एंड पर ट्रैविस हेड भी मौजूद रहे।

फास्ट न्यूज

'धुरंधर' की शूटिंग के दौरान रोए थे अक्षय खन्ना-अर्जुन रामपाल

मुंबई। फिल्म 'धुरंधर' में 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के रीक्रिएशन वाले सीन की शूटिंग के बाद एक्टर अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल बुरी तरह रो पड़े थे। यह बात फिल्म में उनके को-स्टार आर. माधवन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताई। दरअसल, आर. माधवन ने हाल ही में सोनिया शेनॉय के साथ पॉडकास्ट में कहा कि जब वह सीन फिल्माया जा रहा था।

'दो दीवाने शहर में' और 'अस्सी' की धीमी शुरुआत

मुंबई। मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी स्टारर फिल्म 'दो दीवाने शहर में' और तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हुईं, लेकिन पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर सकीं। जहां 'दो दीवाने शहर में' 1.25 करोड़ रुपए कमा सकी, वहीं 'अस्सी' ने सिर्फ 1 करोड़ रुपए की ओपनिंग की। दोनों फिल्मों की पहले दिन की कमाई 13 फरवरी को रिलीज हुई 'ओ रोमियो' के आठवें दिन के कलेक्शन 2.2 करोड़ रुपए से भी कम रही। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'दो दीवाने शहर में' के पहले दिन सुबह के शोज में फिल्म की ऑक्यूपेंसी 55.77% रही, जो दोपहर में घटकर 8.48% और रात में 14.96% तक पहुंच गई। फिल्म को एक इम्परफेक्ट लव स्टोरी के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन ओपनिंग डे पर इसका असर सीमित रहा।

एनएएसए ने माना- सुनीता का अंतरिक्ष में फंसना खतरनाक था

वाशिंगटन। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने माना कि सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में फंसना खतरनाक था। नासा ने इस मिशन को दुर्घटना की टाइप ए कैटेगरी में रखा गया है। इसी कैटेगरी को दुर्घटना की सबसे गंभीर कैटेगरी माना जाता है। चैलेंजर और कोलंबिया शटल दुर्घटनाओं के लिए भी इसी कैटेगरी का इस्तेमाल किया गया था।

जैकी श्रॉफ ने नूतन की 35वीं पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि

एक्टर ने दिवंगत एक्ट्रेस की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें शेयर कर उन्हें किया याद

मुंबई, एजेंसी

बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ ने दिवंगत एक्ट्रेस नूतन की 35वीं पुण्यतिथि पर सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक्टर ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें नूतन की कई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें तस्वीरें शामिल थीं। वीडियो पर लिखा था, "नूतन जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए।" बता दें कि नूतन का जन्म 1936 में हुआ था और 21 फरवरी 1991 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया था। वह 54 साल की थीं। वर्ष 1990 में उन्हें ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था, जिसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ। हालांकि, 1991 में उनकी तबीयत फिर बिगड़ गई थी। नूतन हिंदी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेसेस में थीं। उन्होंने 1945 में अपने पिता की फिल्म नल दमयंती में बाल कलाकार के रूप में कैमरे के सामने पहली बार काम किया। 1950 में मां के निर्देशन में बनी हमारी बेटी से उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस करियर शुरू किया। इसके बाद

1951 में नगीना और हम लोग जैसी फिल्मों ने उन्हें पहचान दिलाई। 1955 में फिल्म सीमा उनकी पहली बड़ी सफलता साबित हुई, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। 1959 में अनाड़ी और सुजाता से उनका करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। 1963 में बिमल रॉय की बंदिनी में उनकी एक्टिंग को भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में गिना जाता है। 1960 और 70 के दशक में छलिया, सरस्वतीचंद्र, मिलन और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों से उन्होंने स्टारडम कायम रखा।

रणवीर सिंह को मिली धमकी के मामले में एक्शन

लॉरेंस गैंग के सदस्य के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी, एक्टर से ₹20 करोड़ मांगे थे

मुंबई, एजेंसी

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को कथित तौर पर उगाही की धमकी देने के मामले में लॉरेंस गैंग के संदिग्ध सदस्य हैरी बॉक्सर के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया है। अधिकारियों ने बताया कि रणवीर सिंह को उनके मैनेजर के फोन नंबर पर व्हाट्सऐप वॉयस नोट के जरिए धमकी मिली थी। मैसेज भेजने वाले ने खुद को हैरी बॉक्सर बताया और 20 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने पुष्टि की कि वॉयस नोट भेजने में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) का इस्तेमाल किया गया, ताकि भेजने वाले की नेटवर्क पहचान और लोकेशन छिपाई जा सके। धमकी भरे ऑडियो क्लिप को वेरिफिकेशन के लिए पंजाब और हरियाणा भेजा गया है। वहीं NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक धमकी भरे मैसेज पर अब तक रणवीर की ओर से कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। इसके बाद 13 फरवरी को रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी को एक और धमकी ऑडियो क्लिप के जरिए मिली। क्लिप में बोलने वाले व्यक्ति ने खुद को हैरी बॉक्सर बताते हुए कहा था, 'अब तुम्हें दिखाएंगे कि हमारी ताकत के आगे तुम्हारी सात पुश्तें भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तुम्हारे सभी मैनेजर कहां रहते हैं, कब आते-जाते हैं और परिवार कहां रहता है, सब पता है। संभल जाओ, वरना एक-एक मैनेजर को निशाना बनाना शुरू करेंगे।' धमकी वाली यह ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामने आने के बाद मुंबई पुलिस ने रणवीर और रोहित शेट्टी के मैनेजरों का बयान दर्ज किया था। हैरी बॉक्सर का असली नाम हरि चंद जाट है, जो लॉरेंस गैंग का एक्टिव मेंबर माना जाता है। हैरी राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला है और पहले जयपुर में बॉक्सिंग कोच था, जिससे उसे बॉक्सर नाम मिला।

रणवीर सिंह को धमकी मिली थी

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह को रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग के बाद 2 फरवरी को धमकी मिली थी। हालांकि, इस खबर की जानकारी 10 फरवरी को मीडिया में आई। धमकी के बाद रणवीर के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। मामला मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। रणवीर और दीपिका ने प्राइवेट सिक्योरिटी भी बढ़ाई। छह हथियार से लैस सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए।

हैरी बॉक्सर का असली नाम हरि चंद जाट है, जो लॉरेंस गैंग का एक्टिव मेंबर माना जाता है। हैरी राजस्थान के अलवर जिले का रहने वाला है और पहले जयपुर में बॉक्सिंग कोच था, जिससे उसे बॉक्सर नाम मिला। उसके खिलाफ राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में जबरन वसूली, लूट और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं।

सेना अब सरकार नहीं चलाती, इतिहास में दखल था, अब सिस्टम अलग है

मुनीर मेरे बॉस नहीं : ख्वाजा आसिफ

म्यूनिख, एजेंसी

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उनके बॉस नहीं हैं। उन्होंने साफ किया कि उनके बॉस प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। 18 फरवरी को फ्रांस 24 इंग्लिश को दिए इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या आसिम मुनीर ही पाकिस्तान की सरकार चला रहे हैं। उन्होंने माना कि अतीत में सेना ने सीधे शासन संभाला था। ख्वाजा आसिफ ने इससे पहले पिछले साल दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान में सरकार और सेना मिलकर देश चलाते हैं। आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल से चलाया जा रहा है। आसिफ पहले भी कई बार हाइब्रिड मॉडल की तारीफ कर चुके हैं। अरब न्यूज को दिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम आदर्श लोकतंत्र नहीं, लेकिन जरूरी है। उन्होंने कहा था कि यह मॉडल पाकिस्तान की आर्थिक और शासन की समस्याओं को हल करने में 'कमाल' कर रहा है। आसिफ ने यह भी कहा कि भारत के साथ युद्ध की संभावना अभी भी खत्म नहीं हुई है। आसिफ ने कहा है कि फिलिस्तीनियों को उनका हक मिले बिना इजराइल से रिश्ते सामान्य करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान अभी इस विकल्प पर विचार भी नहीं कर रहा है। गाजा में संभावित अंतरराष्ट्रीय शांति मिशन में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर उनसे सवाल किया गया।

आसिफ ने कहा, पाकिस्तान का एक सिस्टम है। हमारे इतिहास में ऐसे दौर रहे हैं, जब सेना का सरकार पर नियंत्रण रहा। एक समय ऐसा भी था जब सेना ने दखल देकर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। उन्होंने कहा कि इस समय पाकिस्तान अफगानिस्तान से खतरे, आतंकवाद, भारत के साथ तनाव और कमजोर अर्थव्यवस्था जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे हालात में पाकिस्तानी सेना सरकार का समर्थन कर रही है।

भारत-अफगानिस्तान पर प्रॉक्सी वॉर चलाने का आरोप लगाया

ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमलों को लेकर नई दिल्ली और काबुल की सोच एक जैसी है। आसिफ ने कहा जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में दोबारा कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान की ओर से शांति की कोई ठोस गारंटी नहीं मिलती है, तो पाकिस्तान वहां नए हमले करने से पीछे नहीं हटेगा।

आतंकी हमलों के लिए काबुल को जिम्मेदार ठहराया

इस्लामाबाद की एक शिया मस्जिद में हाल ही में हुए बम धमाके का जिक्र करते हुए आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में लगभग सभी बड़े आतंकी संगठनों की मौजूदगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकवाद रोकने में काबुल सरकार गंभीर नहीं है। उनके मुताबिक इसे सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि मिलीभगत कहना ज्यादा सही होगा। 6 फरवरी को नमाज के दौरान हुए इस आत्मघाती हमले में 31 लोगों की मौत हो गई और 169 लोग घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट समूह ने ली है।

फोन-पे से बिना पिन डाले होंगे यूपीआई पेमेंट

फिंगरप्रिंट और फेस आईडी से कर सकेंगे ₹5000 तक का भुगतान

नई दिल्ली, एजेंसी

डिजिटल पेमेंट दिग्गज फोन-पे (PhonePe) ने अपने यूजर्स के लिए एक खास फीचर लॉन्च किया है। अब यूपीआई (UPI) ट्रांजेक्शन करने के लिए बार-बार 4 या 6 अंकों का पिन (PIN) डालने की जरूरत नहीं होगी। यूजर्स अपने स्मार्टफोन के बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी फिंगरप्रिंट या फेस आईडी का इस्तेमाल करके सीधे भुगतान कर सकेंगे फोन-पे ने बताया कि इस फीचर का मकसद पेमेंट को पहले से ज्यादा सुरक्षित और आसान बनाना है। फिलहाल यह सुविधा एंड्रॉयड यूजर्स के लिए शुरू की गई है, जिसे जल्द ही आईफोन (iOS) यूजर्स के लिए भी रोलआउट किया जाएगा। फोन-पे के अनुसार अक्सर भीड़भाड़ वाली जगहों पर पेमेंट करते समय 'शोल्डर सर्फिंग' (पीछे से किसी का पिन देख लेना) का खतरा रहता था। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से यह रिस्क पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसके अलावा, कई बार यूजर्स अपना यूपीआई पिन भूल जाते हैं या गलत टाइप कर देते हैं, जिससे ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। कंपनी ने इस 'वन-टच' पेमेंट मेथड के लिए एक लिमिट तय की है। यूजर्स बायोमेट्रिक के जरिए 5,000 तक के ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर, अगर भुगतान की राशि 5,000 से ज्यादा होती है, तो सिस्टम पहले की तरह ही यूपीआई पिन मांगेगा।

तेजी : सोना ₹2,300 बढ़कर ₹1.55 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ, चांदी ₹8,000 महंगी हुई

इस हफ्ते सोने-चांदी में बढ़त रही

नई दिल्ली, एजेंसी

देश के सर्राफा बाजार में इस हफ्ते एक बार फिर तेजी का रुख देखने को मिला। सोने और चांदी दोनों की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगातार उतार-चढ़ाव के बीच कीमती धातुओं में निवेश को लेकर बाजार में नई हलचल दिखाई दे रही है। इस सप्ताह सोने की कीमत में 2,300 रुपए की मजबूती आई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना अब 1.55 लाख रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले 13 फरवरी, शुक्रवार को इसका भाव 1.53 लाख रुपए था। साल 2026 की शुरुआत से अब तक सोना करीब 22,000 रुपए महंगा हो चुका है। हालांकि बीच-बीच में मुनाफावसूली और अंतरराष्ट्रीय बाजार के दबाव के कारण उतार-चढ़ाव भी देखने को मिला है। चांदी की कीमतों में भी इस हफ्ते जबरदस्त तेजी रही। एक किलो चांदी का भाव 2.42 लाख रुपए से बढ़कर 2.50 लाख रुपए हो गया है। यानी महज एक हफ्ते में 8,000 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। 2026 में अब तक चांदी करीब 20,000 रुपए महंगी हो चुकी है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि औद्योगिक मांग और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की तलाश ने चांदी को भी मजबूती दी है। इस साल 29 जनवरी को सोने और चांदी दोनों ने ऐतिहासिक स्तर छुआ था। उस दिन 10 ग्राम सोने की कीमत 1.76 लाख रुपए तक पहुंच गई थी, जबकि चांदी ने 3.86 लाख रुपए प्रति किलो का ऑल टाइम हाई दर्ज किया था। हालांकि बाद में कीमतों में कुछ गिरावट आई, लेकिन अब फिर से तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, महंगाई का दबाव, डॉलर में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव जैसे कारक सोने-चांदी को मजबूती दे रहे हैं। निवेशक जोखिम भरे बाजार से निकलकर सुरक्षित विकल्प की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे मांग में इजाफा हो रहा है।हालांकि ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में निवेशकों को बाजार की दिशा, अंतरराष्ट्रीय संकेतों और अपने वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की सलाह दी जा रही है।

सोना खरीदते समय इन 2 बातों का रखें ध्यान

1. सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें: हमेशा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें। ये नंबर अल्फान्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह से हो सकता है- AZ4524। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है।

2. कीमत क्रॉस चेक करें: सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज (जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिए-शन की वेबसाइट) से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग-अलग होता है।

भारतीय मूल की आशा शर्मा माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की सीईओ बनीं

सैन फ्रांसिस्को। भारतीय मूल की आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वे लंबे समय से इस पद को संभाल रहे फिल स्पेंसर की जगह लेंगी। स्पेंसर लगभग 40 साल तक कंपनी के साथ रहने के बाद रिटायर हो रहे हैं। वें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को रिपोर्ट करेंगी। आशा शर्मा माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की कमान संभालने से पहले कंपनी के ही एआई प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट लीडरशिप टीम का हिस्सा थीं। इससे पहले वे मशहूर डिलीवरी फर्म 'इंस्टाकार्ट' में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और 'मेटा' में प्रोडक्ट लीडरशिप जैसे अहम पदों पर रह चुकी हैं। आशा ने मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के कार्लसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से बिजनेस की डिग्री ली है। उन्हें बिजनेस स्केल करने और मुश्किल समय में टीमों को लीड करने का एक्सपर्ट माना जाता है। आशा ने अपना पहला आधिकारिक मेमो भेजा है, जिसमें उन्होंने एक्सबॉक्स के भविष्य और गेमिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर अपनी विजन साफ कर दी है।

1 अप्रैल से कैश में टोल नहीं दे पाएंगे

फास्टैग या यूपीआई से ही होगा पेमेंट, नकद लेनदेन पूरी तरह बंद करने की तैयारी

नई दिल्ली, एजेंसी

देशभर के नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ा बदलाव आने वाला है। National Highways Authority of India (NHAI) 1 अप्रैल 2026 से सभी टोल प्लाजा पर कैश लेनदेन पूरी तरह बंद करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने के बाद टोल का भुगतान केवल FASTag या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से ही किया जा सकेगा। NHAI का यह निर्णय देश के 1,150 से अधिक टोल प्लाजा और एक्सप्रेसवे पर लागू होगा। फिलहाल इन सभी स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम पहले से ही लागू है, लेकिन अब नकद भुगतान को पूरी तरह समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है। अथॉरिटी के अनुसार, टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट के कारण अक्सर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। खासकर पीक ऑवर्स में नकद लेनदेन, छुट्टे पैसों को लेकर विवाद और रसीद प्रक्रिया में देरी से वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। आंकड़ों के मुताबिक, देश में 98% से अधिक वाहनों में FASTag लगा हुआ है। ऐसे में डिजिटल भुगतान को अनिवार्य करना व्यवहारिक कदम माना जा रहा है। यदि कोई वाहन बिना एक्टिव FASTag के FASTag लेन में प्रवेश करता है और नकद भुगतान करता है, तो उससे दोगुना टोल वसूला जाता है। यदि कोई वाहन चालक UPI के जरिए भुगतान करता है, तो लागू टोल दर का 1.25 गुना शुल्क देना होता है। NHAI का मानना है कि पूरी तरह डिजिटल ट्रांजेक्शन से डेटा मैनेजमेंट बेहतर होगा। टोल कलेक्शन का सटीक रिकॉर्ड रखा जा सकेगा और फर्जीवाड़े या राजस्व हानि की संभावना कम होगी। यह पहल केंद्र सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत नेशनल हाईवे नेटवर्क को टेक्नोलॉजी आधारित और हाई-एफिशिएंसी सिस्टम में बदला जा रहा है। आने वाले समय में टोल सिस्टम का यह डिजिटल बदलाव न केवल यात्रियों के लिए सफर को सुगम बनाएगा, बल्कि राजस्व प्रबंधन और यातायात नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यदि कोई वाहन बिना एक्टिव FASTag के FASTag लेन में प्रवेश करता है और नकद भुगतान करता है, तो उससे दोगुना टोल वसूला जाता है।

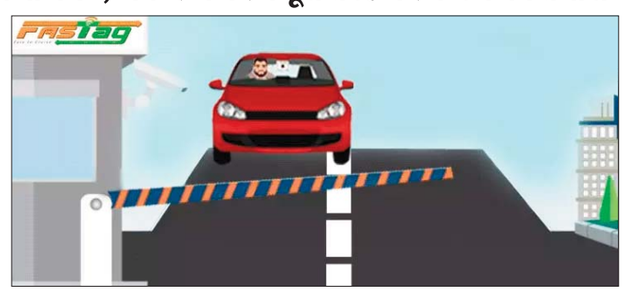

यूजीसी रेगुलेशन पर सवर्ण मोर्चा का उग्र प्रदर्शन

बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, सड़क पर बैठकर विरोध

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में UGC रेगुलेशन के खिलाफ शनिवार को सवर्ण मोर्चा सड़क पर उतर गया। सैकड़ों प्रदर्शनकारी हाथ में तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे थे, पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग करके रोक लिया। इससे नाराज प्रदर्शनकारी कपड़े उतारकर सड़क पर बैठ गए। कुछ बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें खींच-खींचकर नीचे उतारा। कुछ पुलिस बस की छत पर चढ़ने लगे। इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी बहस हुई। धक्का-मुक्की हुई। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बस में ठूस-ठूसकर भरा और इको गार्डन ले गई। प्रदर्शनकारी परिवर्तन चौक से गांधी प्रतिमा जाने वाले थे, लेकिन केडी बाबू स्टेडियम के पास ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस बीच, शहर के ही मोहनलालगंज इलाके में श्रीराजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी ने कहा कि UGC रेगुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है। हम प्रदर्शन न करते लेकिन कुछ संगठन लगातार इसके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसीलिए हमको उनके विरोध में प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हजरतगंज चौराहे पर UGC रेगुलेशन के विरोध में प्रदर्शन से पहले श्रीराजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह 'दीपू' को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। उन्हें उनके घर पर मोहनलालगंज थाने की पुलिस और हरिकेश गढ़ी चौकी इंचार्ज ने बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी।

करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह 'दीपू' को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले पूर्व पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री भी UGC के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि BJP बंट चुकी है। RSS में दो विचारधारा हो गई है जिससे उसमें भी दो-फाड़ है। हम राजनीतिक पार्टी लेकर आ रहे हैं। बीजेपी का विकल्प लेकर आ रहे हैं।

यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ इस्तीफा देने वाले पूर्व बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कहा- सवर्ण और ओबीसी वर्ग भाजपा से छिटक चुका है। हम जल्द ही नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च करेंगे। जनता को भाजपा का विकल्प उपलब्ध कराएंगे। भाजपा सिर्फ विदेशी जनता पार्टी बनकर रह गई है।

परिवर्तन चौक पर लगा लंबा जाम, वाहनों की लंबी कतार लगी

परिवर्तन चौक पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की की वजह से हजरतगंज की ओर जाने वाले रूट पर लंबा जाम लग गया। यही स्थिति हजरतगंज से आने वाले रूट पर रही। परिवर्तन चौक पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली।

प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी की, पुलिस ने उन्हें खींचकर नीचे उतारा।

750 लीटर मिलावटी सरसों तेल और रंग-एसेंस सीज

लखनऊ के बुद्धेश्वर में जनरल स्टोर पर छापेमारी, 600 लीटर राइस ब्रान ऑयल जब्त

- एफएसडीए टीम ने बुद्धेश्वर स्थित शिवम जनरल स्टोर पर छापा मारा।
- मौके से 150 लीटर मिलावटी सरसों तेल और 600 लीटर राइस ब्रान ऑयल बरामद किया गया।

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने शनिवार को बुद्धेश्वर स्थित एक जनरल स्टोर पर छापेमारी की। जांच के दौरान यहां राइस ब्रान ऑयल में कृत्रिम रंग और एसेंस मिलाकर उसे शुद्ध सरसों तेल के रूप में बेचने का खुलासा हुआ। टीम ने मौके से 750 लीटर तेल समेत रंग और एसेंस जब्त कर नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। FSDA टीम ने बुद्धेश्वर स्थित शिवम जनरल स्टोर पर छापा मारा। निरीक्षण के दौरान टीम को संदेह हुआ कि परिसर में बड़े पैमाने पर तेल में मिलावट का काम चल रहा है। जांच में सामने आया कि राइस ब्रान ऑयल में प्रतिबंधित रंग और एसेंस मिलाकर उसे सरसों तेल के रूप में तैयार किया जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक मिलावटखोर राइस ब्रान ऑयल को पीले रंग और तेज गंध देने के लिए कृत्रिम रंग और एसेंस का उपयोग कर रहे थे। इससे उपभोक्ताओं को भ्रमित कर इसे शुद्ध सरसों तेल के रूप में बेचा जाना था। मौके से 150 लीटर मिलावटी सरसों तेल और 600 लीटर राइस ब्रान ऑयल बरामद किया गया। साथ ही प्रयोग में लाए जा रहे कृत्रिम रंग और एसेंस भी जब्त किए गए। FSDA टीम ने सरसों तेल, राइस ब्रान ऑयल, रंग और एसेंस के नमूने विधिवत सील कर राजकीय प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालक (एफबीओ) के खिलाफ नियमों के उल्लंघन और जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के आरोप में FIR दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

फास्ट न्यूज

राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

लखनऊ। लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने VVIP गेस्ट हाउस के सामने से कांग्रेस दफ्तर की ओर कूच किया। इस दौरान पुलिस ने रोड को बैरिकेड करके पूरी तरह जाम कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने 'राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ' और 'राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद' जैसे नारे लगाए और कांग्रेस नेता का पुतला जला दिया।

गाड़ी की टक्कर से युवक की मौत

लखनऊ। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वह राजमिस्त्री का काम करता था। उसकी पहचान संजय यादव के रूप में हुई। शुक्रवार रात किसी तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी थी, जिससे संजय गंभीर रूप से घायल हो गया था। शनिवार सुबह इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। संजय यादव बंथरा के नरेरा गांव के निवासी थे। वह शुक्रवार रात थाना क्षेत्र के रामदासपुर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। हरौनी से सहिजनपुर रेलवे फाटक जाने वाली डिफेंस रोड पर पावर हाउस के पास सामने से आ रही कार ने उसको टक्कर मारी। इससे दाहिना पैट टूटकर अलग हो गया। संजय सड़क पर तड़पने लगा। इस टक्कर में संजय का दाहिना पैर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

लखनऊ नगर निगम के सदन में पार्षदों में तीखी बहस

लखनऊ। लखनऊ नगर निगम का सदन शुरू होते ही भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी बहस और तनातनी हो गई। भाजपा पार्षद के बोलने पर कांग्रेस वाले ने कहा कि आप बार-बार न बोलिए। इसके बाद दोनों पक्षों में स्थिति यहां तक पहुंची कि अन्य पार्षदों को बीच में आना पड़ा। दरअसल, कांग्रेस पार्षद मुकेश सिंह चौहान सदन का एजेंडा न मिलने का विरोध कर रहे थे।

झोलाछाप डॉक्टर ने घर में घुसकर किया रेप

कुशीनगर में लोगों ने हाथ-पैर बांधकर पीटा

तमसा संकेत, एजेंसी

कुशीनगर। कुशीनगर में रेप के आरोप में एक झोलाछाप डॉक्टर की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि वह एक महिला के घर में घुस गया, उससे छेड़छाड़ की और धमकाकर रेप किया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद उसकी पिटाई की गई और साड़ी से उसके हाथ-पैर बांधकर सड़क पर लिटा दिया गया। घटना हनुमानगंज थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिटाई और बंधक बनाने का वीडियो भी सामने आया है। महिला के शोर मचाने पर लोग पहुंचे और आरोपी झोलाछाप डॉक्टर को पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई कर दी। महिला के शोर मचाने पर लोग पहुंचे और आरोपी झोलाछाप डॉक्टर को पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटने के बाद उसके हाथ-पैर साड़ी से बांध दिए। पीड़ित महिला ने बताया- उसके दो बच्चे- एक 5 साल और एक 10 साल- के हैं। पति हैदराबाद कमाते हैं। गुरुवार रात में वह अपने बच्चों के साथ सो रही थी। रात करीब 11 बजे गांव का झोलाछाप डॉक्टर दिनेश मद्धेशिया घर के पीछे के दरवाजे पर पहुंचा और खटखटाने लगा।

बजट सत्र खत्म होते ही फिर खुला विधानसभा भवन, 'लखनऊ दर्शन' बस टूर में लौटी लोकतंत्र की झलक

इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस से पर्यटक अब दोबारा देख सकेंगे ऐतिहासिक विधानसभा

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र समाप्त होते ही राजधानी के पर्यटन प्रेमियों के लिए एक खुशखबरी है। अब 'लखनऊ दर्शन' बस सेवा के जरिए पर्यटक एक बार फिर से भव्य और ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन का भ्रमण कर सकेंगे। बजट सत्र के दौरान सुरक्षा कारणों से विधानसभा भ्रमण अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, लेकिन अब लोकतंत्र का यह दरबार आम लोगों के स्वागत के लिए फिर से तैयार है। यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि, भव्य स्थापत्य, विशाल गुंबद और ऐतिहासिक महत्व से भरपूर विधानसभा भवन राजधानी की पहचान है। इसके दोबारा टूर में शामिल होने से 'लखनऊ दर्शन' और भी आकर्षक हो गया है। लखनऊ दर्शन बस के प्रमुख स्थलों में एक जीपीओ भी है। जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी में सरकारी खजाना लूट की घटना के बाद अंग्रेज सरकार ने इसे बगावत मानते हुए करीब 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। सुरक्षा कारणों से लखनऊ के तत्कालीन रिंग थियेटर (आज का जनरल पोस्ट ऑफिस लखनऊ) में विशेष अदालत बनाई गई, जहां लगभग 10 महीने तक मुकदमा चला। अदालत ने राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान को फांसी, जबकि शचीन्द्रनाथ सान्याल को कालापानी और मन्मथनाथ गुप्त सहित अन्य को कठोर कारावास की सजा सुनाई। आज भी यहां पुरानी निशानियां म्यूजियम में हैं जो पर्यटकों को दिखाई जाती हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, "बजट सत्र की समाप्ति के साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा का भ्रमण दोबारा शुरू किया जा रहा है। 'लखनऊ दर्शन' इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा के जरिए पर्यटक अब राजधानी की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विरासत को करीब से देख सकेंगे। विधानसभा भवन के पुनः शामिल होने से इस टूर का आकर्षण और बढ़ेगा। हमारी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ लोगों को प्रदेश की समृद्ध परंपराओं से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।" उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) की 'लखनऊ दर्शन' इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा प्रतिदिन सुबह और शाम दो पालियों में 1090 चौराहे से संचालित होती है, जो पर्यटकों को राजधानी के प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थलों का भ्रमण कराती है।

डीआईओएस कार्यालय पर आप का हमला

'तानाशाही और कुप्रबंधन से बोर्ड परीक्षा प्रभावित'

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ में बोर्ड परीक्षाओं के बीच जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) कार्यालय को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। Aam Aadmi Party (AAP) ने DIOS कार्यालय के कथित कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और शिक्षकों के मानसिक उत्पीड़न के आरोपों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर विभाग पर गंभीर आरोप लगाए और कई उदाहरणों के साथ स्थिति को चिंताजनक बताया। महेंद्र सिंह के अनुसार, रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज के एक विज्ञान शिक्षक की हाल ही में हार्ट सर्जरी हुई है। डॉक्टरों ने उन्हें पूर्ण विश्राम और तनाव से दूर रहने की सलाह दी है। इसके बावजूद DIOS कार्यालय ने उनकी ड्यूटी घर से करीब 50 किलोमीटर दूर फैजाबाद रोड स्थित अयोध्या मेमोरियल इंटर कॉलेज में लगा दी। बताया गया कि विभाग को शिक्षक की स्वास्थ्य स्थिति से अवगत कराने के बावजूद चार दिन बीत जाने के बाद भी ड्यूटी में बदलाव नहीं किया गया। AAP ने सवाल उठाया कि क्या विभाग किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? जनपद के बप्पा वोकेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज, मोतीलाल इंटर कॉलेज, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, एमकेएसडी, विद्यांत इंटर कॉलेज, सेंटिनल इंटर कॉलेज और गुरुनानक गर्ल्स इंटर कॉलेज सहित कई परीक्षा केंद्रों पर कक्ष निरीक्षकों की कमी बताई गई है। केंद्र व्यवस्थापकों द्वारा संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क कर निरीक्षकों की मांग की जा रही है, लेकिन पर्याप्त संख्या में तैनाती नहीं हो पा रही है। इससे परीक्षा संचालन में गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। महेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि शिक्षकों की कमी का हवाला देकर कई केंद्रों पर उसी विषय के शिक्षक से ड्यूटी कराई जा रही है, जिस विषय की परीक्षा हो रही है। उन्होंने कहा, "नियम स्पष्ट है।

'यूथ हेरिटेज लीडरशिप प्रोग्राम' का आयोजन, युवाओं को विरासत संरक्षण का संदेश

मंत्री जयवीर सिंह बोले- विरासत हमारी पहचान और भविष्य की दिशा

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारतीय विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय "यूथ हेरिटेज लीडरशिप प्रोग्राम" का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय (संस्कृति विभाग) द्वारा आयोजित किया गया। भारतीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण व प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से चल रहे कार्यक्रमों की इसी श्रृंखला में यह पहल की गई। कार्यक्रम का आयोजन इतिहास संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के महत्व से परिचित कराना और उन्हें विरासत संरक्षण के लिए नेतृत्वकर्ता के रूप में तैयार करना था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों को ऐतिहासिक स्थलों का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। विद्यार्थियों ने राजधानी लखनऊ की छतर मंजिल और जनरल कोठी, कैसरबाग का भ्रमण किया। इस दौरान इन स्थलों के इतिहास, स्थापत्य शैली और संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी सरल और स्पष्ट भाषा में दी गई, ताकि छात्र इन धरोहरों को बेहतर तरीके से समझ सकें। इस दौरान निदेशक सुश्री रेनू द्विवेदी ने विद्यार्थियों को विरासत की परिभाषा, स्वरूप, प्रकृति और उसकी पहचान के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने संवाद के माध्यम से समझाया कि सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही विद्यार्थियों को अपनी विरासत के प्रति जागरूक, संवेदनशील और जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम पर अपने विचार प्रकट करते हुए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि "इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण कराना नहीं है, बल्कि युवाओं को अपनी विरासत से भावनात्मक रूप से जोड़ना है। ताकि वे इन धरोहरों को समझें और उन पर गर्व करें। उन्होंने बताया विरासत केवल अतीत की याद नहीं, बल्कि हमारी पहचान और भविष्य की दिशा भी है। इसलिए युवा पीढ़ी जागरूक और संवेदनशील बनकर सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाएं।" इस मौके पर जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालक विद्यालय और जय प्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय के कक्षा 9वीं और 11वीं के लगभग 70 छात्र-छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में इतिहास संस्थान से सुश्री सुयशा जी सहित पुरातत्व निदेशालय के अधिकारी, शिक्षकगण और विद्यालय के कर्मचारी भी मौजूद रहे।

वारदात : दादी के मायके शादी में गई थी ■ घर से 200 मीटर दूर खून से लथपथ मिली

8 साल की बच्ची से रेप, हालत नाजुक

- शादी समारोह के बाहर सुबह सन्नाटा पसरा रहा।
- सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया- आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।

तमसा संकेत, एजेंसी

गोरखपुर। गोरखपुर में 8 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। मासूम अपनी दादी के मायके एक शादी में गई थी। शादी स्थल से करीब 200 मीटर दूर बच्ची खून से लथपथ मिली। परिजन उसे लेकर स्थानीय अस्पताल पहुंचे लेकिन उसकी हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना शनिवार तड़के पीपीगंज थानाक्षेत्र की है। मासूम सिद्धार्थनगर की रहने वाली है। परिजन की तहरीर पर रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। परिजन के मुताबिक, जयमाला के बाद उसे ढूंढ़ने लगे तो वह नहीं मिली। ड्रोन वीडियो रिकॉर्डिंग को खंगाला गया तो वह गांव के ही एक व्यक्ति के साथ जाती दिखी थी। सिद्धार्थनगर की रहने वाली पीड़िता की दादी का मायके गोरखपुर के पीपीगंज क्षेत्र के एक गांव में है। दादी के भतीजी की शादी शुक्रवार को थी। इसमें वह अपने दादी के साथ पहुंची थी। दादी के अनुसार, जयमाला कार्यक्रम के बाद साढ़े 11 बच्ची अचानक उनकी पोती गायब हो गई। परिवार के लोग उसे खोजने लगे लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद ड्रोन से की जा रही रिकॉर्डिंग देखी गई। इसमें आरोपी अशोक निषाद उर्फ टुनटुन (20) के साथ बच्ची जाती दिखाई दी। परिवार के साथ गांव के लोग भी बच्ची को खोजने लगे। देर रात में शादी समारोह स्थल से करीब 200 मीटर दूर सूनसान जगह पर बच्ची खून से लथपथ मिली। परिजन उसे लेकर आनन फानन में स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल लाया गया। यहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डॉक्टर्स के अनुसार, बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है।

> सीओ कैंपियरगंज सीओ अनुराग सिंह ने बताया- शनिवार तड़के 3 बजे 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की 112 पर सूचना मिली थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित बच्ची के बाबा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आसपास के लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी अशोक निषाद को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस ने आरोपी अशोक को अरेस्ट किया है। शादी के दिन ड्रोन रिकॉर्डिंग में बच्ची को लेकर जाते दिखा था।

पृष्ठ 01 का शेष...

460 करोड़ ...

सीएम योगी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 2.51 लाख किसान परिवारों को मिली 285 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति को संबल बताया। कहा कि फसल को सूखे-अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। जब हम फसल का बीमा कराते हैं तो जरूरत पर रिटर्न भी मिलता है। आपदा के कारण नुकसान हुआ तो भरपाई होती है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि योजना के तहत पहले केवल किसान कवर होता था, उसके परिवार के सदस्य, बटाईदार, सह किसान कवर नहीं होते थे। हमारी सरकार में 1000 करोड़ से अधिक की धनराशि के जरिए किसान या उसके परिवार के सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। किसी मनुष्य की कमी की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन सरकार संबल देने के लिए खड़ी हो सकती है। आपदा प्रभावित 3500 पीड़ित किसानों, सह किसानों, पारिवारिक सदस्यों, बटाईदारों आदि को आज लाभान्वित किया गया है। इससे पहले 16 जून 2025 को 11,690 किसानों व आश्रितों को 561.86 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि कल तक यह पैसा सभी किसानों या आश्रित परिवारों के खाते में पहुंच जाए। 10 फरवरी को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ एमओयू किया गया है, जिसमें आपदा मित्र को तीन वर्ष के लिए 5 लाख का बीमा कवर प्रदान किया गया है। प्रदेश में अभी तक 2959 युवा स्वयंसेवक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं, शेष का प्रशिक्षण भी आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम ने कहा कि पहले आपदा आने पर वर्षों तक पीड़ितों को कोई पूछता तक नहीं था। उन्हें क्षतिपूर्ति तक नहीं मिल पाती थी। 2015-16 में एक बार किसी किसान के खाते में दो रुपये, किसी के खाते में चार रुपये आए थे। हमारा प्रयास है कि बाढ़, आकाशीय बिजली, आगजनी जैसी आपदा आते ही 24 घंटे के भीतर पीड़ित के खाते में पैसा पहुंच जाए।

अजित पवार के ...

उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है। मैं आपसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के मामले में तुरंत कार्रवाई करने का निवेदन करता हूं। कंपनी VSR और उनकी पार्टी के बीच संबंधों को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। इन संबंधों की जांच किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से कराई जानी चाहिए, जरूरत हो तो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की मदद भी ली जाए। आपने हमेशा अजित दादा और उनके देश के प्रति योगदान का सम्मान किया है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जांच पूरी होने तक राम मोहन नायडू से मंत्री पद से इस्तीफा लेने को कहा जाए। हादसे में शामिल विमान की कंपनी का सीधा संबंध तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) से है।

राजस्थान-एमपी ...

जबकि पिछले साल अक्टूबर में SIR शुरू होने से पहले 2,78,50,855 वोटर्स थे। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने का काम जारी रहेगा। बीएलओ के पास फॉर्म भरकर अब भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया जा सकता है। इसके लिए फॉर्म 6 भरना होगा। वोटर पोर्टल https://voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन भी नाम जुड़वा सकते हैं। EC ने असम में हुए स्पेशल रिवीजन (SR) 2026 के तहत फाइनल वोटर लिस्ट जारी की थी। EC के मुताबिक, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में 2.43 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। अब राज्य में कुल 2,49,58,139 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या 2,52,01,624 थी। स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया के बाद लिस्ट में 2,43,485 नाम हटाए गए हैं। अब फाइनल लिस्ट में 1,24,82,213 पुरुष, 1,24,75,583 महिलाएं और 343 थर्ड-जेंडर शामिल हैं। यह चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है।

ब्राजीली राष्ट्रपति ...

इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा, विदेश सचिव विक्रम मिसरी और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल मौजूद थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा के बीच होने वाली द्विपक्षीय मुलाकात में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ्स पर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

अविमुक्तेश्वरानंद ...

हम दर-दर भटक रहे थे। पुलिस के पास जा रहे थे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इसलिए न्याय के मंदिर में आए। आज लगा कि न्याय अभी जिंदा है। न्यायालय ने हमें आज न्याय दिया। मैं अब साफ-साफ कहना चाहता हूं कि शिष्यों के साथ यौन शोषण और समलैंगिक अपराध किया गया। इसकी पुष्टि न्यायालय ने कर दी है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया। कहा, हर मामले में FIR दर्ज करना अनिवार्य नहीं होता। मजिस्ट्रेट को अपने विवेक से तय करना होता है कि FIR का निर्देश दिया जाए या शिकायत के रूप में आगे बढ़ाया जाए। यदि मामले में पुलिस जांच जरूरी हो, तो FIR दर्ज कर जांच करना उचित होता है।कोर्ट ने कहा, आरोप गंभीर और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं।

एनकाउंटर का डर दिखाकर 20 लाख वसूलने वाले दरोगा अरेस्ट

प्रयागराज में दोनों को दौड़ाकर पकड़ा, कारोबारी को किडनैप किया था

तमसा संकेत, एजेंसी

मेरठ। मेरठ में एनकाउंटर का डर दिखाकर धागा कारोबारी से 20 लाख रुपये वसूलने वाले दो दरोगाओं को पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों दरोगा पिछले 10 दिनों से फरार चल रहे थे। मेरठ पुलिस को इनपुट मिला था कि शुक्रवार को दोनों आरोपी प्रयागराज में एक वकील से मिलने पहुंचेंगे। वे वकील के जरिए हाईकोर्ट में अपील कर गिरफ्तारी से बचने की तैयारी में थे। सूचना मिलते ही मेरठ पुलिस की टीम प्रयागराज पहुंच गई। शुक्रवार शाम जैसे ही दोनों दरोगा-लोकेंद्र साहू और महेश गंगवार-वकील के चेंबर में पहुंचे, पुलिस ने उन्हें घेर लिया। दोनों ने भागने की कोशिश की लेकिन पुलिसकर्मियों ने दौड़ाकर उन्हें पकड़ लिया। दोनों दरोगा लोहियानगर थाने में तैनात थे। मेरठ शहर के इस्लामाबाद रिक्शा रोड निवासी रासिख की एमएसआरएस टेक्सटाइल नाम की फर्म है। कारोबारी ने बताया- 8 आठ दिसंबर को मैं नौचंदी के पास से अपनी दुकान से लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में आजाद रोड पर एक कार आकर रुकी। उसमें पुलिस के दो दरोगा थे। एक कार से नीचे उतरा और जबरन मुझे गाड़ी में डाल लिया। धमकाते हुए कहा- फंडिंग करता है। तेरे पर रासुका लगाएंगे। दोनों दरोगा उसे हापुड़ ले गए। उस पर हवाला का पैसा मंगाकर फंडिंग करने का आरोप लगाया। कारोबारी ने बताया- रास्ते भर उसे बुरी तरह टॉर्चर किया, जिससे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। हापुड़ ले जाकर गोली मारने की धमकी दी। हवाला में पैसा लगाने का आरोप लगाया।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com
स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।
सम्पादक : विद्यादेवी
समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा
समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं है।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676